INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) Representations from Association of Indian Fishery Industry have been received requesting rehabilitation of the sick deep-sea fishing units.

(b) No, Sir.

(c) No legal constraint is envisaged in implementation of rehabilitation package announced in April, 1991 which was further liberalised in June, 1992.

Licences for brewing beer

283. SHRI DIGVIJAY SINGH:
SHRI ISH DUTT YADAV:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that certain State Government have issued licences for brewing beer whereas the Central Government propose to delicence the Beer Industry;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) Government's reaction with regard thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI TARUN GOGOI): (a) to (c) According to the legal position, the Central Government alone is competent to issue a licence for brewing beer. However, it is a fact that certain State Governments have issued permissions for installing breweries. The detailed information regarding these permissions is being collected from the States and will be laid on the Table of the House as soon as it is available. Government will also finalise its reaction after full information is available.

At present there is no proposal under consideration with the Government to delicense beer industry.

रोजगार समस्या हल करने के लिए कृषि उद्योग

284. डा. जिनेन्द्र कुमार जैन :
श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 मई, 1993 के "आब्जर्वर" में एग्रो-इंडस्ट्री कैन सोल्व इंडियाज जाब प्राब्लम ए स्टडी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी है कि देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार और विकास करके देश में बेरोजगारी की बढ़ती हुई समस्या को हल किया जा सकता है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह अनुमान लगाया है कि कितने लोगों को रोजगार दिया जा सकता है और इस प्रयोजन के लिए इस उद्योग में कितनी पूंजी का निवेश किये जाने की आवश्यकता है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में बहुत अधिक रोजगार उत्पन्न करने की संभावना है । यह अनुमान है कि करीब 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने से इन उद्योगों में आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान करीब 10 लाख श्रम वर्ष (मैन-इयर्स, के बराबर रोजगार उत्पन्न होगा ।

खाद्य क्षेत्रों की परियोजनाओं का कार्यान्वयन

285. श्री राम जेठमलानी ;
श्रीमती सुषमा स्वराज ;

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ग) क्या सरकार का ध्यान 11 मई, 1993 के "दि इक्नोमिक टाइम्स" में,

"ओनली 25 आउट आफ 2,042 फूड सैक्टर प्रोजेक्टस एक्जीक्यूटिड इन टू इयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है)

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पिछले दो वर्षों में सरकार द्वारा स्वीकृत 2,042 परियोजनाओं ने से अब तक केवल 25 की ही कार्यान्वित किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर ना" हो इस संबंध में तथ्य क्या है ?

खाद्य प्रसंकरण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) :

(क) जी, हां ।

(ख) से (घ) नवीन तम सूचना के अनुसार उद्यमियों द्वारा खाद्य उत्पादों के संबंध में वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने के लिए 97 ज्ञापन प्रस्तुत किए गये हैं। परियोज.ाओं के कार्यान्वियन में सामान्यतया 2–3 घर्ष का समय लग जाता है क्योंकि यह विभिन्न घटकों जैसे बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, उत्पाद की किस्म, राज्य स्तर पर विभिन्न स्वीकृतियों, वित्त की व्यवस्था आदि पर निर्भर करता है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और विकास के लिए राष्ट्रीय नीति

286. **श्री राम जेठमलानी** : : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ज यह सच है कि सरकार ने देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के विस्तार और विकास के लिए एक राष्ट्रीय नीति घोषित करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस नीति की घोषणा करने से पूव किसानों, उद्योगपतियों और अन्य विशेषज्ञों के साथ इस मामले में परामर्श करना चाहती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की उक्त योजना का ब्यौरा क्या है ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरुण गोगोई) : (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण पर एक नीति तैयार करने के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है । इस नीति में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में रोजगार के अवसर और आमदनी बढ़ाने की दृष्टि से खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के त्वरित विकास एवं संवर्धन, फसलोत्तर नुकसान को कम करने, उद्योग और किसानों के बीच उत्पादक संपर्क स्थापित करने, प्रसंस्कृत खाद्यों के निर्यात को बढ़ाने और सामान्यतः कृषि एवं संबंधित क्रिया-कलापों के त्पादक कार्यों को समर्थन देने के बारे में उल्लेख किया जायेगा । सभी संबंधितों से विधिवत परामर्श करके इसे अंतिम रूप दिया जायेगा ।

Demand for transplantation of human organs

287. SHRI KRISHAN LAL SHARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the demand for transplantation of human organs in the country is on the increase;

(b) whether it is also a fact that a number of human organs go waste as a result of fatal road accidents;

(c) whether Government propose to enact a law permitting instantaneous removal of organs from victims of road accidents under a qualification, presumed consent; and